



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 1992/अग्रहायण 18, 1914
No. 243] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 1992/AGRAHAYANA 18, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1992

सं. जे.-12014/1/92-जे.आर. :—न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार अपने सतत प्रयास के भाग के रूप में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की वांछनीयता पर कुछ समय से विचार कर रही थी। सरकार ने अब सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के अनुसरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार ने संस्था अंतर्नियम तथा अकादमी का स्थान, इसका कार्य क्षेत्र, चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा

वित्त प्रदान करने के तरीके जैसे अन्य मामलों पर विचार करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

2. समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश | अध्यक्ष |
| 2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस.आर. पांडेयान | सदस्य |
| 3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस.सी. अग्रवाल | सदस्य |
| 4. न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. न्यायमूर्ति श्री जे.के. नाथूर, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. सचिव, भारत सरकार, न्याय विभाग | सदस्य |

7. सचिव, भारत सरकार, विवादी विभाग	सदस्य
8. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
9. सचिव, भारत सरकार, व्यय विभाग	सदस्य
10. डा. आर. एन. माधव मेनन, निदेशक, राष्ट्रीय विधि विद्यालय, भारत विश्वविद्यालय, बंगलूर	सदस्य
11. डा. निर्मला खोटे, विधि संकाय, बंबई विश्व-विद्यालय	सदस्य
12. महापंजायक, उच्चतम न्यायालय	संयोजक

3. सोसायटी के पंजीकृत हो जाने पर समिति का कार्य-विधि समाप्त हो जाएगी।

1. सरकारी सदस्य उपरोक्त कार्य के संबंध में उनके द्वारा उनके कार्यालयों से की गई यात्राओं के लिए उन पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5. समिति के गैर सरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार के प्रथम ग्रेड के अधिकारियों को अनुमति होता है।

यात्रा-प्राप्ति दिया जाता है कि संकाय को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. पी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th December, 1992

F. No. J-12014/1/92-JR.—The Government of India had been considering for sometime, as part of its continuing endeavour to improve the judicial system, the desirability of establishing an All-India level training institution for the training of Judicial Officers. The Government have now decided to set up a National Judicial Academy as a Society, registered under the Societies Registration Act (Act XXI of 1860).

In pursuance of this decision, the Government have, in consultation with the Chief Justice of India, decided to constitute an Ad-hoc Committee to consider the Articles of Association and such other matters as the location of the Academy, its Faculty, courses to be adopted, and mode of financing, etc.

2. The Committee will have the following members :—

1. The Chief Justice of India	Chairman
2. Shri Justice S. R. Pandian, Judge, Supreme Court of India	Member
3. Shri Justice S. C. Agrawal, Judge, Supreme Court of India	Member
4. Shri Justice M. K. Mukherjee, Chief Justice, High Court of Allahabad	Member
5. Shri Justice J. K. Mathur, Judge, High Court of Allahabad	Member
6. Secretary to the Govt. of India, Department of Justice	Member
7. Secretary to the Govt. of India, Department of Legal Affairs	Member
8. Secretary to the Govt. of India, Deptt. of Personnel & Training	Member
9. Secretary to the Govt. of India, Department of Expenditure	Member
10. Dr. N. R. Madhava Menon, Director, National Law School of India, University, Bangalore	Member
11. Dr. Nirmala Khody, Faculty of Law, University of Bombay	Member
12. The Registrar General of Supreme Court of India	Convener

3. The tenure of the Committee will come to an end as soon as the Society is registered.

4. The official members will be entitled to draw TA/DA etc. for the journeys undertaken by them in connection with the above assignment from their respective offices in accordance with the rules applicable to them.

5. The non-official members of the Committee will be entitled to TA/DA for their journeys to attend meetings as admissible to officers of the First Grade of the Government of India.

ORDER : Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. P. SINGH, Jt. Secy.